



2026:AHC:54675-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या- 1615 वर्ष 2026

मेसर्स जुबैर एंटरप्राइजेज याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और एक अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुमित कुमार गुप्ता, वेदिका नाथ, यशोनिधि शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., धनंजय अवस्थी, प्रियंका मिधा

न्यायालय सं - 3

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन

1. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सुश्री वेदिका नाथ और राजस्व की अधिवक्ता सुश्री प्रियंका मिधा को सुना।
2. याचिकाकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने वाले अधीक्षक, रैंज XXV द्वारा पारित दिनांक 30.07.2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। यह आदेश दिनांक 19.07.2025 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार पारित किया गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा दायर निरसन आवेदन के कारण के बारे में बताया गया है जिसे 13.01.2026 को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, कोई कमी / त्रुटि नहीं है।
4. गुण-दोष के आधार पर, हम ध्यान दें, 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म 'फर्जी' थी, इसका जवाब 27.05.2025 को मांगा गया था। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आक्षेपित आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण बताए बिना पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता फर्म फर्जी थी। सुलभ संदर्भ के लिए, दिनांक 30.07.2025 का अंतरिम आदेश निम्नानुसार निकाला गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"संदर्भ संख्या: ZA090725869898B

दिनांक: 30/07/2025

सेवा में,

नाम: जुबैर इडारीज

पता: वार्ड संख्या-11 रगौल पूर्वी, तहसील रोड, मौदाहा, हमीरपुर,
उत्तर प्रदेश, 210507 तिथि:

जीएसटीआईएन/यूआईएन: 09ACEPI9120K1ZH

आवेदन संदर्भ संख्या-(एआरएन): AA090725141882W

दिनांक:

पंजीकरण रद्द करने का आदेश

इसमें दिनांक 19/07/2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का
संदर्भ है।

जबकि कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया
गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर, आप
व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से
उपस्थित नहीं हुए थे, और जबकि, इस कार्यालय के पास उपलब्ध
अभिलेखों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका
पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता है।

1. अन्य

टिप्पणियां:

करदाता ने अपने जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए जारी
नोटिस का जवाब नहीं दिया है।

आपके पंजीकरण को रद्द करने की प्रभावी तिथि 19/07/2025 है।

2. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक
दस्तावेज़ देखें। - लागू नहीं



3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. आपको अपने सभी लंबित रिटर्न प्रस्तुत करने होंगे।

5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पंजीकरण को रद्द करने से इस अधिनियम के तहत कर और अन्य देय राशि का भुगतान करने या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के दायित्व को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, चाहे इस तरह के कर और अन्य बकाया रद्दीकरण की तारीख से पहले या बाद में निर्धारित किए गए हों या नहीं।

स्थान: सीबीआईसी

दिनांक: 30/07/2025"

5. आदेश के एक सादे अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने के लिए बिल्कुल कोई कारण नहीं बताया गया है। पंजीकरण रद्द करने के लिए इस तरह के कठोर कदम उठाने से पहले न केवल कारणों को सौंपने की आवश्यकता होती है, व्यावहारिक रूप से पंजीकृत व्यक्ति के व्यापार में संलग्न होने के अधिकार को छीन लेता है। यहां, सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 29 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के आधार पर, ऐसे कदम केवल अधिनियम की धारा 129 के तहत निर्दिष्ट कारणों के लिए ही उठाए जा सकते हैं।

6. जिस हद तक आक्षेपित आदेश कारणों से रहित है, यह कानून की नजर में कोई आदेश नहीं है। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफलता या कार्यवाही में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने में विफलता नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का आधार प्रदान कर सकती है, हालांकि, पंजीकरण रद्द करने का यह कभी भी



कारण नहीं हो सकता है। नतीजतन, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

मामला प्रतिपक्षी संख्या-2/अधीक्षक, सी.जी.एस.टी. रेंज XXV को भेज दिया जाता है।

7. इस संबंध में, याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का अंतिम जवाब दाखिल कर सकता है। इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस के साथ किसी भी तारीख को याचिकाकर्ता को सुनने के लिए आगे बढ़ेगा। याचिकाकर्ता ऐसी कार्यवाही में सहयोग करने का वचन देता है। उचित तर्कसंगत आदेश 30.04.2026 को या उससे पहले पारित किया जा सकता है।

8. तदनुसार, प्रस्तुत याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 17, 2026

प्रखर

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)